International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 13-02-2026, Accepted: 14-03-2026, Published: 30-03-2026
Volume 12, Issue 1, 2026, Page No. 490-492

नागरिक समाज

Dr. Ashutosh Sharma
Assistant Professor, Government Model Degree College, Devganpure, Panwari, Mahoba, Uttar Pradesh, India

सारांश
नागरिक समाज (Civil Society) सरकार, बाजार और परिवार के दायरे से बाहर सक्रिय रहने वाले स्वैच्छिक, स्वतंत्र और गैर–सरकारी संगठनों का एक ऐसा समूह है, जो सामाजिक हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सेतु का कार्य करता है। ऐतिहासिक रूप से सिसरो से लेकर आधुनिक विचारकों तक इसकी अवधारणा में व्यापक बदलाव आए हैं। जहाँ जॉन लॉक इसे नागरिक सरकार के समतुल्य मानते हैं, वहीं ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों, हीगल और कार्ल मार्क्स ने इसे मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों और निजी संपत्ति के क्षेत्र से जोड़ा। इसके विपरीत, एंटोनियो ग्रामशी ने इसे राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम देते हुए 'वैचारिक आधिपत्य' (Hegemony) और 'सहमति के सृजन' का मुख्य केंद्र माना। अलेक्सिस डी टॉकविले और रॉबर्ट पुटनैम जैसे विचारक इसे मजबूत लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता के लिए अनिवार्य मानते हैं। वर्तमान में यह क्षेत्र एक ओर जहाँ सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है, वहीं दूसरी ओर कुछ संगठनों की संदेहास्पद और गैर–जिम्मेदाराना गतिविधियां इसकी नकारात्मक भूमिका को भी रेखांकित करती हैं।

मूलशब्द: नागरिक समाज (Civil Society), गैर–सरकारी संगठन (NGOs), लोकतंत्र (Democracy) आधिपत्य/प्राधान्य (Hegemony), नागरिक सहभागिता (Civic Participation), स्वयं सहायता समूह (SHGs)

नागरिक समाज उन गैर सरकारी, स्वैच्छिक और स्वतन्त्र संगठनों, समूहों और संस्थानों का समूह है जो सरकार, बाजार (व्यवसाय) और परिवार के दायरे से बाहर काम करते हैं अर्थात यह समाज का वह हिस्सा है जहाँ लोग समाज हितों, उद्देश्यों और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। यह सरकार और आम जनता के बीच एक मजबूत कड़ी या सेतु का काम करता है।

नागरिक समाज के प्रमुक घटक/अंग हैं– स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार, पर्यावरण आदि से सम्बन्धित NGO, स्थानीय–सामूहिक मुद्दों और सामाजिक सुधारों के लिए आवाज उठाने वाले नागरिक समूह और छात्र संगठन, व्यावसायिक संगठन, सामाजिक कल्याण का कार्य करने वाली परोपकारी एवं धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरण में संलग्न स्वयं सहायता समूह (SHGs), जागरूकता एवं नीति विश्लेषण में संलग्न मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया एवं थिंक टैंक आदि। एक स्वस्थ लोकतन्त्र और समाज के विकास के लिए नागरिक समाज की भूनिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

नागरिक समाज का अर्थ सामूहिक स्वतन्त्रता है, जो अधिकार हम अकेले नहीं पा सकते, उन्हें हम सामूहिक रूप से पाने की कोशिश करते हैं, इसमें विशेष है– 1. भिन्नता 2. सहिष्णुता एवं 3. सहमति।

नागरिक समाज का सिद्धान्त सिसरो ने भी दिया। यह ग्रीक शब्द ब्पअपस "Societas" से बना है, परन्तु अर्थ भिन्न था। उस समय राज्य एवं सरकार दोनों आते थे। आगे चलकर जॉन लॉक ने नागरिक समाज नहीं वरन् नागरिक सरकार की बात की, वहाँ नागरिक समाज का मतलब जो राज्य नहीं है। लॉक ने नागरिक समाज एवं सरकार दोनों का इस्तेमाल किया है।

ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थॉमस पेन, एडम स्मिथ एवं एडम फर्ग्यूसन ने इसका अर्थ आर्थिक कार्य से लिया है। आधुनिक काल मे हीगल मानता है कि 'Civil Society in interposed between family and stat'। हीगल कहता है कि विकास का प्रथम चरण परिवार है, यह प्यार पर आधारित है, इसको परोपकारिता कहते हैं। इसके अगले चरण पर आर्थिक क्रिया के लिए प्रतिस्पर्धा होती है जो प्रतिवाद है। यह प्रतिवाद नागरिक समाज है, इसमें लोग स्वार्थी होते है और प्रतियोगिता होती है। राज्य संवाद है, जो परिवार और नागरिक समाज के दोषों को दूर करता है। इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक हो जाते हैं। प्रतिवाद के रूप में नागरिक समाज इन दोनों (परिवार एवं राज्य) के बीच है। अत: हीगल की नागरिक समाज की अवधारणा सिर्फ आर्थिक थी।

कार्ल मार्क्स ने नागरिक समाज का अर्थ निजी सम्पत्ति एवं बाजार सम्बन्धों से लिया है। बाद में उसने इस शब्द को निरर्थक माना है, यह शब्द उसके प्रारम्भ वाले ग्रन्थों में मिलता है।

1930 में ग्रामशी ने नागरिक समाज के राजनीतिक अर्थ की बात की है। उसने हीगल की मान्यता के विरूद्ध इसे राजनीतिक बनाया। ग्रामशी ने नागरिक समाज को राजनीतिक क्रिया की गतिविधि कहा है।

हीगल ने इसको आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनाया जबकि ग्रामशी ने इसे राजनैतिक आधार दिया। ग्रामशी मानता है कि लोगों की चेतना भी महत्वपूर्ण होती है। सन्पन्न एवं विपन्न के बीच प्राधान्य की बात होती है। इस प्राधान्यता में आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्ष भूमिका निभाते हैं। हर शासक वर्ग सांस्कृतिक हथियार को अपनाता है, चुनौती देने का प्रयास, प्रति–प्राधान्य का प्रयास पिछड़े करते है, ये नागरिक समाज में आते हैं। ग्रामशी ने नागरिक समाज का आधुनिक सिद्धान्त दिया है।

नागरिक समाज को कभी कभी तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। संगठन की स्वतंत्रता पर आधारित होने के कारण नागरिक समाज अन्य क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करता है। इसके अन्तर्गत नागरिक समाज, गैर–सरकारी संगठन एवं अन्य संगठन आते हैं। नागरिक समाज के लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनैतिक संगठन एवं सामान्य सामाजिक विकास पर बल देते है। इसका विकास उदार लोकतन्त्र में ज्यादा होता है एवं यह सविनय अवज्ञा के विरूद्ध एक अवरोध का कार्य करती है। नागरिक समाज का सार अपने लोगों को स्वयं संगठित करना है। सिसरो व कुछ प्राचीन ग्रीक विचारकों ने इसकी तुलना राज्य से की है। इसके अन्तर्गत वे राज्य आते थे जो काफी विकसित, शहरी, खुद की विधि संहिताओं वाले थे तथा जिनमें नागरिकता के गुण होते थे। उस अवधारणा मे जो बर्बर थे एवं स्वतन्त्र शहरी संस्कृति नहीं थी, वे नागरिक समाज नहीं थे। संक्षेप में, नागरिक समाज का मतलब

परम्परागत विचार में नागरिक सहभागिता था, नागरिक कानून के द्वारा शासित होना सभ्य समाज का गुण माना जाता था। समझौतावादी चिंतन में, मुख्यत: जॉन लॉक के लेखन में राजनीतिक या सभ्य समाज, पितृसत्तात्मक सत्ता एवं प्राकृतिक अवस्था का विरोधी माना जाता था। लॉक जब नागरिक सरकार की बात करता था तो उसका मतलब नागरिक समाज से है। इस प्रकार नागरिक समाज राजनैतिक रूप से सक्रिय लोगों का अखाड़ा है जो सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। किन्तु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इसकी अवधारणा में परिवर्तन आया, जब नागरिक समाज और राज्य के सम्बन्धों को अलग करके देखा गया।

यहाँ ब्रिटिश सामाजिक चिन्तन मुख्य रूप से प्रभावित करता है। टॉमस पेन, एडम स्मिथ, एडम फर्गुसन के लेखन ने नागरिक समाज के क्षेत्र को राज्य के क्षेत्र से भिन्न माना गया है। इन विचारकों ने यह माना कि नागरिक समाज का स्वयं का एक क्षेत्र है जो राज्य से भिन्न है, इस तरह के अंतर को स्थापित करने में राजनीतिक अर्थशास्त्र का बहुत हाथ है। ज्यादातर लेखकों ने नागरिक समाज शब्द का प्रयोग समय समय पर भिन्न अर्थ में किया है। परन्तु ये लेखक नागरिक समाज के अर्थ को राज्य से पूर्णत: अलग करने मे समर्थ नहीं हो पाये, इसका श्रेय हीगल को जाता है।

हीगल ने परिवार को वाद, नागरिक समाज को प्रतिवाद एवं राज्य को संवाद बताया है। हीगल ने नागरिक समाज के सिद्धान्त को आधुनिक बनाया। हीगल– "Philosophy of Right" में कहता है कि नागरिक समाज नैतिक जीवन का क्षेत्र है जो परिवार एवं राज्य से अन्त: सम्बन्धित है। ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का अनुसरण करते हुए हीगल कहता है कि नागरिक समाज में अधिकांशत: आर्थिक ताकतें उनकी स्वतन्त्र क्रियाएं एवं व्यक्ति का स्वयं का हित प्रमुख होता है। लेकिन नागरिक समाज के अन्तर्गत वे सामाजिक एवं नागरिक संस्थाएं भी आती है जो आर्थिक जीवन को नियंत्रित करती है एवं शिक्षा के द्वारा राज्य के अन्दर एक विवेकसंगत जीवन जीने की स्थिति पैदा करती है। कार्ल मार्क्स ने हीगल के प्रति अपना ऋण व्यक्त किया है। उसने नागरिक समाज के अर्थ को संकुचित करते हुए, निजी सम्पत्ति एवं बाजार सम्बन्धों के स्वायत्र क्षेत्र के समतुल्य कर दिया है। नागरिक समाज वह है जहाँ आर्थिक क्रियाएं होती है। मार्क्स कहता है कि "The autonomy of civil society is to be sought in political economy"। नागरिक समाज का प्रयोग बाद के ग्रन्थों में मार्क्स ने नहीं किया। यही कारण है कि बाद के सभी मार्क्सवादियों ने नागरिक समाज पर चर्चा नहीं की। नागरिक समाज को मार्क्स के बाद लोकप्रिय बनाने में एलेक्स डी. टकिविले की "Democracy in America" है। उसने लिखा कि यदि राज्य न भी रहे तो संगठन चलता रहेगा। यदि राज्य न रहेगा तो भी संगठन सारे कार्य सम्पादित करता है और कानून एवं व्यवस्था चलती रहेगी, उसने अमरीकी संगठनों की बड़ी प्रशंसा की। उसने अमरीकी लोकतंत्र की सफलता में इन संगठनों का हाथ माना है। टॉकविले के काफी बाद ग्रामशी ने इसको पुन: प्रयोग में ला दिया। इसे पुन: 20वीं सदी के पूर्व भाग में प्रतिष्ठा प्रदान की। ग्रामशी हीगल से आगे जाकर नागरिक समाज को आर्थिक क्षेत्र से हटा कर राज्य के क्षेत्र में इसकी व्याख्या करता है। मार्क्सवादी मौलिक अभिविन्यास को रखते हुए ग्रामशी हीगल के विचारों की इस अवधारणा को पुन: स्थापित करता है। वास्तव में ग्रामशी ही ऐसा दार्शनिक था जिसने नागरिक समाज की अवधारणा को आर्थिक आयाम से अलग करके राज्य के साथ जोड़ने का प्रयास किया। Civil Society is that part of the state concern are not with the rule. नागरिक समाज वह भाग है जो ताकत के प्रयोग या औपचारिक शासन से सम्बद्ध नहीं है, यह सहमति के सृजन से सम्बन्धित है। वह शक्ति न कहकर प्रधानता शब्द का प्रयोग करता है। वह कहता है कि शासक वर्ग सिर्फ दण्ड से ही शासन नहीं करता वरन् मुख्यत: सहमति से शासन करते हैं, इसका एक सांस्कृतिक पहलू है। जिससे समाज कानून के पालन के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। आम आदमी कानून का अभ्यस्त होता है, वह अनुशासन को आत्मसात् करता है। यह नागरिक समाज का ही एक पहलू है जो राज्य का भी अंग है। यह औपचारिक शासन से सम्बन्धित है। यह जनता में एक सहमति तैयार करता है। पहले भारत में ब्राह्मणों का सर्वसम्मति से सम्मान किया जाता था। इसमें धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसी से उच्च वर्ग की प्राधान्यता स्थापित होती है। ग्रामशी भी प्राधान्यता के प्रतिवाद की बात करती है, जब ऐसा सांस्कृतिक विकास हो, जो पहले से जमी सभ्यता को हटाकर खुद प्रभुत्व स्थापित करता हो, यह सांस्कृतिक राजनीति का क्षेत्र ही नागरिक समाज है। ग्रामशी का मानना है कि नागरिक समाज की संस्थायें– चर्च, गुरूद्वारा, मंदिर एवं मस्जिद, विद्यालय, व्यापारिक संगठन, अन्य संगठन, निम्न वर्ग पर प्रधानता बनाये हुए हैं। ट्रेड यूनियन्स पर सभी लोग कब्जा करना चाहते हैं। ताकि वे अपनी बात को मनवा सके, हर दल अपना ट्रेड यूनियन रखते हैं, जैसे– भा.ज.पा. का भारतीय मजदूर संघ, कांग्रेस का INTUC आदि।

ये सभी उसी प्राधान्यता का एक अंग है क्योंकि लोग हमेशा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नागरिक समाज की ही संस्थायें है। नागरिक समाज में धार्मिक अधिष्ठान, विद्यालय के द्वारा शासक वर्ग समाज में अपनी प्रधानता जमाता है। केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के हिसाब से नीति बदलती है। सत्ता पक्ष चाहता है कि देश का विकास हो एवं विपक्ष अस्थिरता चाहता है, ये नागरिक समाज के ही दो लोग है। अधिसत्ता को खत्म करने के लिए विपक्षी दल पूरा प्रयास करते हैं। यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा आधिपत्य को चुनौती दी जाती है। ग्रामशी की इस अवधारणा के कारण 1950–60 में बहुत से लोगों व सगठनों ने एकाधिकारवादी शासकों के खिलाफ आन्दोलन चलाया था।

नागरिक समाज में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका–

शोधों में यह बात सामने आयी है कि दबाव समूह जैसे व्यापारिक संगठन, मजदूर संघ, चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स, प्रजातीय संगठन, वकील संघ, व्यापार संघ एवं अन्य विभिन्न संगठन, ये सभी नागरिक समाज के अन्तर्गत गिने जाते हैं और ये संगठन नागरिक समाज को मजबूत करने में सहायक होते हैं। कभी–कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये गैर सरकारी संगठन नागरिक समाज को कमजोर भी कर देते हैं। इनकी दोहरी भूमिका है।

क्या नागरिक समाज लोकतंत्र को मजबूत बनाता है?

नागरिक समाज राज्य में अनुशासन स्थापित करता है एवं इस बात की सुरक्षा प्रदान करता है कि नागरिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए एवं नागरिक सहभागिता में भी वृद्धि की जाए। राबर्ट पुटनैम एवं अन्य विद्वानों ने कहा है कि नागरिक समाज जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा क्योंकि नागरिक समाज राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाता है। जहाँ नागरिक समाज नहीं है वहाँ राजनीतिक भागीदारी कम होती है एवं लोकतंत्र कमजोर होता है। पुटनैम की पुस्तक "BowlingA lone" में अमरीकी सहभागिता में कमी को दिखाया गया है क्योंकि उम्मीदवारों के चुनाव में जनता भाग ही नहीं लेती है। व्यक्तिवाद, नौकरी की तलाश, छोटा परिवार, मनोरंजन के साधनों का विकास, इलेक्ट्रानिक मीडिया ने नागरिक समाज में राजनीतिक सहभागिता घटायी है। यदि लोग एक दूसरे से मेलजोल नहीं करेंगे तो नागरिक समाज कमजोर होगा। ग्रामशी मानते हैं कि आधुनिकता की अवधारणा भी नागरिक समाज को

कमजोर करती है। विभिन्न संगठन चुनाव में मतदाता को प्रेरित करते हैं। पहले लोगों में नागरिक समाज का सिद्धान्त मजबूत था क्योंकि लोगों की राजनीतिक सहभागिता मजबूत थी।

क्या लोकतंत्र मजबूत सभ्य समाज को सुनिश्चित करता है?

ये बात भी सही है कि जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ नागरिक समाज मजबूत होता है। व्यक्ति पूरे संगठन के माध्यम से अपनी बात करता है। तानाशाही में व्यक्ति संगठन बना ही नहीं सकता। जैसे– भारत में सभी धार्मिक संगठन संक्रिय है क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है जबकि चीन, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्रमश: कम्यूनिस्ट पार्टी की तानाशाही तथा सैनिक प्रभुत्व के अधीन छद्म लोकतंत्र है।

क्या नागरिक समाज आर्थिक विकास के लिए जरूरी है?

नागरिक समाज आर्थिक सफलता में सहायक है। जिन लोगों का जीवन कठिन था, गैर सरकारी संगठनों ने उनके जीवन को आरामदायक एवं उन्नतिशील बनाया। सामाजिक बुराई व अपराधों की रोकथाम एवं विभिन्न समस्याओं के निदान गैर सरकारी संगठनों ने आसान किया है। यह एक सामाजिक कार्य है लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी है। तमाम गैर सरकारी संगठन भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। यह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जैसे– एमनेस्टी इण्टरनेशनल, ग्रीन पीस। इन लोगों व संगठनों के सभी गलत कार्यों को विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। यह इनकी भूमिका पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नागरिक समाज, समाज के निर्माण में एवं लोकतन्त्र की गतिशीलता के लिए एक अत्यन्त एक महत्वपूर्ण तत्व है।

संदर्भ सूची

1. माइकल एडवर्ड: सिविल सोसाइटी, 2009, पौलिटी प्रेस यू0एस0, ISBN–978–0–7456–4585–81
2. घनश्याम शाह: डेमोक्रेसी, सिविल सोसाटी एण्ड गवर्नेस, 2019, सेज पब्लिशिंग हाउस, ISBN– 9353281792
3. सुदीप्त कविराज : सिविल सोसिटी: हिस्ट्री एण्ड पासिबिलिटी, 2001, एवं सुनील खिलनानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन/ISBN–05216334431
4. जॉन कीन : सिविल सोसाइटी : ओल्ड इमेज, न्यू विजन, 2004, पॉलिटी प्रेस, लन्दन, ISBN–978–0–7456–6741–61
5. सम्पादित, माइकल एडवर्ड: द ऑक्सफोर्ड हैण्डबुक ऑफ सिविल सोसाइटी, 2011, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लन्दन।
6. माइकल एडवर्ड एण्ड जॉन गेवेन्टा : ग्लोबल सिटीजन एक्शन, 2001 लीन राइनर पब्लिशर, कौलटैन्जे, ISBN–1–55587–968–31
7. नीरा चन्दोक: स्टेट एण्ड सिविल सोसाइटी, 1995, सेज पब्लिकेशन, नयी दिल्ली, ISBN–1–08039–9246–71
8. टी.के. ओमेन: नेशन, सिविल सोसाइटी एण्ड सोशल मूवमेण्ट्स: एशेज दून पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, 2004, सेज पब्लिकेशन, नयी दिल्ली/लन्दन, ISBN–0–7619–9828–4